All Online Learning www.allonlinelearning.com

Part XVIII: Emergency Provisions

Part XVIII of the Constitution of India deals with Emergency Provisions. It contains provisions regarding the circumstances under which the Union or a State can declare a state of emergency and the consequences that follow such a declaration.

Article 352 provides for the proclamation of a national emergency by the President on the grounds of war, external aggression or armed rebellion. When a national emergency is declared, the Executive power of the Union extends to giving directions to any State regarding the manner in which the executive power thereof is to be exercised.

Article 353 provides for the power of the President to make regulations for the peace and good government of any part of the territory of India in the event of a national emergency.

Article 354 provides for the suspension of the right to move the court for the enforcement of the rights conferred by Part III of the Constitution (fundamental rights) during a national emergency.

Article 355 provides for the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution.

Article 356 provides for the proclamation of a state of emergency in a State, by the President, on the grounds of failure of the constitutional machinery in a State. When a state of emergency is declared, the President's rule is imposed in the State, and the President can make such regulations as he thinks fit for the peace and good governance of the State.

Article 357 provides for the power of the President to issue directives for the purpose of giving effect to the provisions of the Constitution in relation to the state of emergency declared in a State.

Overall, Part XVIII of the Constitution of India lays down the provisions regarding the circumstances under which the Union or a State can declare a state of emergency and the consequences that follow such a declaration, and aims to ensure the protection of the country against external aggression, internal disturbance, and failure of the constitutional machinery in a State.

भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान

भारत के संविधान का भाग XVIII आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। इसमें उन परिस्थितियों के बारे में प्रावधान शामिल हैं जिनके तहत संघ या राज्य आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकते हैं और ऐसी घोषणा के बाद होने वाले परिणाम।



www.allonlinelearning.com

All Online Learning www.allonlinelearning.com

अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है। जब एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को उस तरीके के बारे में निर्देश देने तक होता है जिसमें कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना है।

अनुच्छेद 353 राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारत के किसी भी हिस्से की शांति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 354 एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार के निलंबन का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के लिए संघ के कर्तव्य को प्रदान करता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है।

अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में आपातकाल की स्थिति की घोषणा का प्रावधान करता है। जब आपातकाल की स्थिति घोषित की जाती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकता है जो वह राज्य की शांति और सुशासन के लिए उचित समझे।

अनुच्छेद 357 किसी राज्य में घोषित आपातकाल की स्थिति के संबंध में संविधान के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से निर्देश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान करता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग XVIII उन परिस्थितियों के प्रावधानों को निर्धारित करता है जिसके तहत संघ या राज्य आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकते हैं और परिणाम जो इस तरह की घोषणा का पालन करते हैं, और इसका उद्देश्य बाहरी आक्रमण के खिलाफ देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। , आंतरिक गडबडी, और एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता।

